

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,  
(सामान्य) वन मंडल दमोह, मध्यप्रदेश।

विषय:- दमोह जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना अंतर्गत दमोह-कटनी से जोगीडाबर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.855 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 0.58615 हेक्टेयर) म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, दमोह को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/129457/2021)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./82 दिनांक 19.01.2022

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, सागर एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 10,50,444/- is to be paid for the 0.855 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- आवेदक संस्थान द्वारा बिना अनुमति के अवैध उत्खनन का कार्य 0.2 हेक्टेयर में किया गया है। अतः प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप दापिंडक नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि ₹0 2,45,718/- आवेदक संस्थान से वसूल कर कैम्पा मद में जमा कराई जावे।
- 4- प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा बिना अनुमति के अवैध उत्खनन का कार्य किया गया है। प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भारत सरकार की नवीन गाइड लाईन (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु क्रमांक 1.21(i) b के अनुसार कार्यवाही की जावे।
- 5- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

-2-

- 6- प्रकरण में 14 वृक्ष काटे जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 140 वृक्षों की राशि 2000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि रु. 2,80,000/- कैम्पा मद में जमा कराई जावे।
- 7- User agency shall restrict the 14 felling of trees.
- 8- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- 9- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 10- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 11- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 12- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 13- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 14- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 15- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 16- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 17- No work shall be done during night.
- 18- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 10,50,444/-, दार्पणिक नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 2,45,718/- एवं 140 वृक्षों की रोपण की राशि रूपये 2,80,000/- आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे एवं वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर दमोह का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/ क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

*29/2/2022*  
(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1108 / 2022 / 10-11 / 1162

प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29/3/22

- 1— मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त, सागर, मध्यप्रदेश।
- 2— महाप्रबन्धक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2, एच.आई.जी.-17, विवेकानन्द कॉलोनी, दमोह, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*8/3/2022*  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबन्ध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल